मध्यप्रदेश की ग्रीन इनर्जी कॉरीडोर कार्य योजना तैयार

2100 करोड़ रूपए लागत के प्रथम चरण में 400 केवी के तीन एवं 220 केवी के सात सब स्टेशन बनेंगे

मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के द्वारा प्रदेश की नवकरणीय विधुत परियोजनाओं की बिजली निकासी एवं ट्रांसमिशन सिस्टम के सुदृढ़ीकरण एवं मध्यप्रदेश के ट्रांसमिशन सिस्टम से अंतर्संबंधता हेतु व्यापक ग्रीन इनर्जी कॉरीडोर कार्य योजना तैयार की गई है। इस कार्य योजना की अनुमानित लागत 4 हजार 700 करोड़ रूपए है, जिसमें ट्रांसमिशन सिस्टम के सुदृढ़ीकरण के कार्य 3 हजार 575 करोड़ रूपए एवं नवकरणीय विद्युत परियोजनाओं की प्रदेश की ट्रांसमिशन सिस्टम से अंतर्संबंधता के कार्य 1 हजार 125 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत से करवाए जाएगें। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश में आगामी पाच वर्षों में 5 हजार 847 मेगावाट की नवकरणीय विद्युत परियोजनाएं स्थापित होने वाली है। इन परियोजनाओं में सोलर विद्युत परियोजना के अंतर्गत 2588 मेगावाट, पवन (विंड) विद्युत परियोजना के अंतर्गत 2704 मेगावाट, लघु सूक्ष्म (मिनी-माइक्रो) जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत 282 मेगावाट एवं जैव ईधन (बॉयोमास) के अंतर्गत 271 मेगावाट बिजली उत्पादन की संभावना है।

मध्यप्रदेश में ट्रांसमिशन सिस्टम सुदृढ़ीकरण के कार्य दो चरणों में करने की योजना बनाई गई है। प्रथम चरण की लागत 2100 करोड़ रूपए एवं द्वितीय चरण की लागत 1475 करोड़ रूपए अनुमानित को गई है।

प्रथम चरण को आगामी तीन वर्षों में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। प्रथम चरण में प्रदेश की संबद्ध नवकरणीय विद्युत परियोजनाओं की क्षमता लगभग 4100 मेगावाट हो जाएगी। प्रथम चरण की कार्य योजना वर्ष 2019-20 तक पूर्ण होने की संभावना है।

योजना के प्रथम चरण में 400 केवी के तीन सब स्टेशन मंदसौर, सागर व उज्जैन में बनाए जाएंगे एवं 400 केवी की 690 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइनों का नेटवर्क तैयार किया जाएगा। कार्य योजना में 220 केवी के सात सब स्टेशन सेंधवा, जावरा, गुड़गांव, कानवन, रतनगढ़, सुसनेर व सैलाना में बनाए जाएंगे एवं 220 केवी की 1 हजार 196 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन का नया नेटवर्क तैयार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 132 केवी की 956 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइनों के नए नेटवर्क के साथ 132 केवी के दो अतिरिक्त ट्रांसफार्मर भी स्थापित किए जाएंगे।

प्रथम चरण के लिए जर्मनी का केएफडब्ल्यू डेब्लपमेंट बैंक परियोजना की अनुमानित लागत का 40 प्रतिशत अंश साफ्ट लोन के रूप में 840 करोड़ रूपए (124 मिलियन यूरो) प्रदत्त करेगा। वहीं मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी को राष्ट्रीय स्वच्छ ऊजां निधि (एनसीईएफ-नेशनल क्लीन इनर्जी फंड) से 40 प्रतिशत अंश के रूप में 840 करोड़ रूपए का अनुदान प्राप्त होगा। प्रथम चरण के लिए मध्यप्रदेश शासन के द्वारा 20 प्रतिशत अंश के रूप में 420 करोड़ रूपए की राशि प्रदान की जाएगी। केएफडब्ल्यू डेब्लपमेंट बैंक एवं भारत शासन के आर्थिक मामलों के विभाग के बीच ऋण अनुबंध इस वर्ष 30 जून को हस्ताक्षरित किया गया है।